शिमला से प्रकाशित

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 28 – 5 मई 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या सुक्खू सरकार संकट में है मुकेश अग्निहोत्री की पोस्ट से उठी चर्चा?

➤ क्या चन्द्र कुमार और राजेश धर्माणी की टिप्पणियों को हल्के में लिया जा सकता है?

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार का अपने ही भार से दम फूलने लगा है? क्या सरकार की स्थिरता प्रश्नित होती जा रही है? क्या कांग्रेस हाईकमान अब भी हिमाचल के हालात को नजर अंदाज कर देगी? यह सारे सवाल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट के सामने आने से उठे हैं।

मुकेश ने लिखा है की **साजिशों का दौर है – झूठ के पांव नही होते।** यह लिखने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि साजिशें रची जा रही हैं भले ही वह झूठी हों। लेकिन यह सवाल अपने में ही गंभीर हो जाता है कि कुछ लोग झूठी सजिशें रचने लगे हुए हैं। अब यह सवाल आता है कि यह साजिशें क्या हो सकती हैं? कौन लोग यह कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले सन्देह विपक्ष पर जाता है कि वह सरकार को गिराने के लिये साजिशों की रणनीति अपनाये। राज्यसभा चुनाव के समय सरकार गिराने का प्रयास हो चुका है और वह प्रयास भाजपा के ही नाम लगा था। लेकिन उस साजिश में उन अपनों की भूमिका बड़ी थी जो सरकार से नाराज चल रहे थे और उनकी नाराजगी को हाईकमान तक ने भी नजरअंदाज कर दिया था। जबकि उनकी हर शिकायत जायज थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सरकार में समायोजन नहीं हो पा रहा है। उस समय गिरने के कगार

साजिशों का दौर.
...झूठ के पाँव नहीं होते।

पर पहुंची सरकार को भाजपा ने ही बचाया था। आज भी भाजपा का सरकार को यह सहयोग बराबर मिला हुआ है। क्योंकि देहरा उपचुनाव में 78 लाख रुपया सरकारी अदारों द्वारा बांटे जाने की शिकायत राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद भी विपक्ष उस पर खामोश है। केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ यह बड़ा आरोप है कि वह विपक्ष की सरकारों को ई.डी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से अस्थिर करने का प्रयास करती है। हिमाचल में भी ईडी, सीबीआई और आयकर एजेंसियों ने दखल दिया और हमीरपुर तथा नादौन में छापेमारी हुई। दो लोग ईडी की हिरासत में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद यह मामला आगे नहीं बढ़ा है। इसको भी राजनीतिक पण्डित सरकार को भाजपा के सक्रिय सहयोग का ही प्रमाण मान रहे हैं। बल्कि जब राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए और अकेले हिमाचल के ही मुख्यमंत्री शामिल हुए थे तब भी विश्लेषकों का माथा ठनका था।

इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश भाजपा सुक्खू सरकार को अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं करेगी। कांग्रेस से भाजपा में गये लोग इन प्रयासों में अलग-थलग पड़ जाएंगे यह तय है। ऐसे में जब साजिशें रचे जाने का दर्द अन्दर से ही छलक कर सामने आ जाये तो उसको भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दिसम्बर 2022 में बनी थी और नवम्बर 2024 में प्रदेश जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणीयां भंग कर दी गई है। इस दौरान हुये लोकसभा चुनाव में सरकार होते हुये भी कांग्रेस चारों सीटें हार गयी। एकमात्र राज्यसभा सीट के चुनाव में भी सरकार हार गयी। इस सीट पर कांग्रेस से भाजपाई हुये हर्ष महाजन चुनाव जीत गये। हर्ष महाजन कांग्रेस में जब थे तब वह कांग्रेस में किन लोगों के निकटस्थ थे और किन लोगों से आज भी उनके घनिष्ठ रिश्ते हैं उसकी ओर ध्यान दिये बिना प्रदेश कांग्रेस की आज की स्थिति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जब कोई विधायक या सांसद बन जाता है तभी से उसे पुनः सत्ता में लौटने की स्वभाविक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस दिशा में वह लगातार नजर बनाये रहता है कि क्या सरकार की कारगुजारी से वह पुनः सांसद विधायक बन पायेगा। जब उसे इस दिशा में यह सन्देश होने लगता जाता है कि शायद ऐसा नहीं हो पायेगा तब वह सरकार के प्रति मुखर होना शुरू कर देता है। आज हिमाचल सरकार और संगठन को लेकर इस मुखरता की स्थितियां बनने लग पड़ी हैं। यह सरकार कर्मचारीयों और बेरोजगार युवाओं के सहयोग से बनी थी। परन्तु आज कर्मचारी ही इस सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने पर विवश हो गया है। बिजली कर्मचारी पिछले काफी समय से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। प्राइमरी शिक्षक धरने प्रदर्शन पर बैठ गये हैं। सचिवालय कर्मचारी कब फिर से मुखर हो जायें कोई कह नहीं सकता। प्रदेश में एक बड़े कर्मचारी आन्दोलन के आसार बनते जा रहे हैं। प्रदेश ऐसे वित्तीय संकट से गुजर रहा है कि वेतन और पैन्शन के लिये नारेबाजी करनी पड़ रही है।

स्वभाविक है कि जब कोई सरकार इस तरह के दौर में पहुंच चुकी हो तो उसके विधायक अपने को कैसे सुरक्षित समझ पाएंगे। सरकार ऐसे में जिस हाईकमान के रहमों-करम पर टिकी होती है उसे बरगलाये रखने में हर तरह के हथकण्डे इस्तेमाल करती ही है। हिमाचल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यह राजेश धर्मानी और चन्द्र कुमार की टिप्पणियों से स्पष्ट हो जाता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक कुलदीप राठौर के तेवर भी इसी दिशा के संकेतक हैं। ऐसे में जब मुकेश अग्निहोत्री साजिश की बात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि शायद हाईकमान के सामने कुछ लोगों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई हों। लेकिन आने वाले दिनों में हाईकमान के सामने यह खुलकर स्पष्ट हो जाने की संभावना प्रबल होती जा रही है कि भाजपा के सहयोग से ही सरकार बची हुई है तब स्थितियां एकदम बदल जायेंगी। क्योंकि चार महीने में सरकार का वित्तीय संकट इतना बड़ा हो जायेगा कि तब केन्द्र के सीधे हस्ताक्षेप की स्थिति पैदा हो जायेगी। उस समय सरकार का अस्तित्व सही में खतरे में आ जायेगा।

एचपीटीडीसी ने पहली बार रिकॉर्ड 100 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश अर्जित किया: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। वर्तमान प्रदेश सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने पहली बार 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऐतिहासिक लाभांश अर्जित कर मील पत्थर हासिल किया है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एचपीटीडीसी और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निगम के 78 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 107 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निगम के होटलों और रेस्तरां के प्रभावी प्रबंधन, नियमित रख-रखाव और परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीटीडीसी द्वारा अर्जित लाभ के फलस्वरूप निगम पिछले अढ़ाई वर्ष के दौरान पेंशनभोगियों को 41 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षों के दौरान केवल 26 करोड़ रुपये वितरित किए थे। उन्होंने अधिकारियों को निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में और अधिक सुधार लाने तथा उपयोग में नहीं लाई जा रही निगम की संपतियों को संचालन व मुरम्मत आधार पर निजी क्षेत्र में लीज पर देने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने एचपीटीडीसी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के मध्य एचपीटीडीसी के होटलों में राशन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित हुए समझौता ज्ञापन की सराहना की।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की और इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके और इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2415 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है जिससे बेहतर पर्यटन अधोसंरचना, वे-साइड एमीनिटिज और अन्य साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने पर्यटन विभाग को स्थानीय लोगों को फूड वेन उपलब्ध करवाने और राज्य में स्थानीय पर्यटन मार्गो पर हॉपऑन, हॉपऑफ लग्जरी बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभाग को मंडी जिला में शिवधाम के निर्माण कार्य तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए रेणुका झील क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क सुविधा के लिए हेलीपोर्ट का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा, शिमला और भुंतर हवाई अड्डों की विस्तार परियोजनाओं की भी समीक्षा की ताकि राज्य में पर्यटकों को बेहतर हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो।

एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, विधायक सुरेश कुमार, प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक पर्यटन विवेक भाटिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता में वृद्धि

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जा रही मासिक वित्तीय सहायता में वृद्धि की है।

पूर्व में यह सहायता राशि 3000 रुपये प्रतिमाह थी जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किया गया है यह बढ़ी हुई वित्तीय सहायता 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा उन सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं को मिलेगी जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और राज्य या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने बादल फटने से व्यक्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला चंबा के चेली गांव के समीप डोंडरा नाला में बीती रात बादल फटने की घटना में एक व्यक्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

इस घटना में प्रभावित परिवार को 25,000 रुपये की अंतरिम राहत राशि प्रदान की गई है। प्रारम्भिक आकलन के अनुसार बादल फटने से आई बाढ़ में लगभग 150 भेड़-बकरियां बही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्व समस्याओं के निवारण में सफल साबित हो रही हैं राजस्व लोक अदालतें

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने की नवोन्मेषी पहल की है जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। राज्य में अक्तूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच कुल 3,25,926 लंबित राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। इससे प्रदेश सरकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की कार्यशैली प्रदर्शित हो रही है।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि के दौरान 2,75,004 इंतकाल मामले, 16,258 तकसीम मामले, 27,404 निशानदेही मामले और 7,260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार आयोजित इस प्रकार की राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के राजस्व संबंधी मामलों को हल किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व लोक अदालतों के नियमित आयोजन से लोगों को नियमित राजस्व मामलों के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही है। सरकार के जनहितैषी प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्व सेवाओं के वितरण में दक्षता सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने निर्देशानुसार सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए तेजी से डिजिटल टूल और कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सशक्त शासन पारिस्थितिकी प्रणाली बनाना है।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, पहली बार अक्तूबर 2023 में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालतों को लंबित राजस्व मामलों को हल करने के लिए नियमित अंतराल में आयोजित किया जा रहा है जिसमें तहसील और उप-तहसील स्तर पर समयबद्ध समस्याओं का निवारण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों का सफल आयोजन शासन को और अधिक कुशल, सहभागी और समावेशी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

आधार आधारित प्रमाणीकरण पर कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने आईटी भवन, मैहली, शिमला में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल पुलिस और पंजीयकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

यह कार्यशाला पुलिस और पंजीयकों को आधार में नवीनतम प्रौद्योगिकी के समावेश से परिचित करवाने के दृष्टिगत आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बताया गया कि आधार को किसी निवासी की पहचान के सत्यापन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। कार्यशाला में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग, समग्र शिक्षा, डाक विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बीएसएनएल के लगभग 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आधार पारिस्थितिकी तंत्र, नियम और विनियम, प्रमाणीकरण मॉड्यूल, आधार नामांकन और अद्यतन के लिए वैध दस्तावेज, 5 और 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट और दस्तावेज अद्यतन से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर यूआईडीएआई के निदेशक जगदीश कुमार ने कहा कि आधार का सत्यापन ऑनलाईन और ऑफलाईन माध्यम द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आधार को आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ एम-आधार एप्लिकेशन से भी सत्यापित किया जा सकता है। इस दौरान आधार सत्यापन म डयूल पर लाइव डेमो भी प्रदर्शित किया गया। सार्वजनिक सेवाओं के त्वरित वितरण में आधार की प्रभावशीलता को दर्शाने के लिए 'डिजी यात्रा' और 'जीवन प्रमाण' के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कोई भी सरकारी या निजी विभाग सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान के क्षेत्र में सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू कर सकता है।

जगदीश कुमार ने कहा कि इस तरह के सत्र नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाएंगे ताकि प्रशासन को यूआईडीएआई के नवीनतम विकास बारे अवगत करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि आधार आधारित प्रमाणीकरण के उपयोग को बढ़ाने और निवासियों को सेवा वितरण के उच्चतम मानक सुनिश्चित करने की दिशा में यह कार्यशाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत निर्वाचन आयोग सिंगल प्वाइंट ऐप करेगा लॉन्च

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। नया वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म, ईसीआइएनइटी, ईसीआई के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन्स को एकीकृत और पुनर्निर्देशित करेगा।

ईसीआइएनइटी सभी चुनाव संबंधित गतिविधियों के लिए एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऐप डाउनलोड करने, नेविगेट करने और विभिन्न लॉगिन याद रखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

ईसीआइएनइटी उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्ट फोन पर प्रासंगिक चुनावी डाटा तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसमें प्राधिकृत ईसीआई अधिकारी द्वारा सटीक डाटा दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी विवाद की स्थिति में, वैधानिक प्रपत्रों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डाटा ही मान्य होगा।

ईसीआइएनइटी में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम, केवाईसी ऐप और अन्य मौजूदा ऐप शामिल होंगे। इससे लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और चुनाव प्रणाली से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, मतदान अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, ईआरओ और जिला चुनाव अधिकारी लाभान्वित होंगे।

ईसीआइएनइटी अपने विकास के अन्तिम स्तर पर है और इसकी प्रभावशीलता तथा साइबर सुरक्षा के दृष्टिगत विकसित किया जा रहा है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मजदूर दिवस पर श्रमिकों को दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड धर्मशाला द्वारा मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा की कंस्ट्रक्शन साइट में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया किया गया जिसमें 400 से ज्यादा श्रमिकों ने भाग लिया। जिसमें उन्हें कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया एवं पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी के साथ साथ केवाईसी के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। जिला कानूनी सलाहकार पैनल द्वारा श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया और कानूनी सलाह के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी लोकेश शर्मा एवं जिला कार्यालय श्रमिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने चमियाना स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आईपीडी सेवाओं का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी सेवाओं का शुभारम्भ किया। आईजीएमसी शिमला में मरीजों की बढ़ती संख्या तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी तथा प्लास्टिक सर्जरी विभागों को आईजीएमसी से चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आगामी दो माह में कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी सीटीवीएस सेवाएं भी इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को अस्पताल तक जाने वाली सड़क का और सुधार करने के निर्देश भी दिए तथा कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए परिवहन सुविधाएं भी सुदृढ की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चमियाना अस्पताल काफी समय से निर्माणाधीन है, लेकिन इसे पूरा करने का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस कार्य को पूरा कर रही है तथा निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की क्षमता 337 बिस्तरों की है तथा इसमें उच्च स्तरीय ऑपरेशन थियेटर और कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। आगामी छह माह में यह अस्पताल पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चमियाना अस्पताल के साथ-साथ सभी मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर रही है, ताकि राज्य में ही मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इससे मरीजों का समय और पैसा भी बचेगा। उन्होंने कहा कि चमियाना राज्य का ऐसा पहला अस्पताल होगा, जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होगी तथा इसके बाद जिला कांगड़ा के टांडा अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा टांडा, हमीरपुर और नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि मरीजों को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान की

900 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर की अफवाहें निराधार

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिमला पुलिस ने राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े 900 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है और ऐसी अफवाहें निराधार हैं।

उन्होंने बताया कि संघ के केवल पांच पदाधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने और गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के मुद्दों को हल करने के लिए संघ के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी।

लोक निर्माण मंत्री ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से भेंट की

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान से भेंट की।

विक्रमादित्य सिंह ने केन्द्रीय राज्य मंत्री से पीएमजीएसवाई-4 में शामिल करने के लिए सत्यापन के दृष्टिगत लंबित 637 बस्तियों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि राज्य में 57 प्रतिशत सड़कें पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित की गई हैं और इन सड़कों के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, इसके बावजूद राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अधिक धन की आवश्यकता है। उन्होंने सड़कों के रख-रखाव के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की भी मांग की।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-1 के तहत निर्मित तीन सड़कों के उन्नयन करने की आवश्यकता है तथा इन सड़कों को पीएमजीएसवाई-4 में जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 के तहत सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा पीएमजीएसवाई-1 के तहत डोडरा-क्वार और बड़ा-भंगाल क्षेत्र के चार सड़क परियोजनाओं के कार्य को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कमलेश पासवान ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। उन्होंने कहा कि राज्य 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, फिर भी हिमाचल को इससे क्या मिला? एसजेवीएनएल 6,700 करोड़ रुपये की कंपनी बन गई है, लेकिन हमें पूछना चाहिए कि हिमाचल को क्या मिला?

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा पानी को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन पानी हिमाचल से बह रहा है।

बदले में हमें क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री ने यह बात न्यू शिमला के सेक्टर-5 में 18 करोड़ रुपये की लागत से बनी पार्किंग के उद्घाटन अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि तीन मंजिला इस पार्किंग में 50 से अधिक वाहन खड़े हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 करोड़ रुपये की लागत से नई पार्किंग सुविधा की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि न्यू शिमला में एक और पार्किंग सुविधा के निर्माण, सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन यहीं रहती हैं, उनका बचपन इसी इलाके में बीता है और उनकी राजनीतिक यात्रा भी यहीं से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आज जहां सेक्टर 5 है, वहां पैदल चलने के लिए रास्ते हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि समय के साथ इस इलाके में काफी विकास हुआ है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वर्तमान सरकार को विरासत में मिली वित्तीय चुनौतियों के संदर्भ में कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो राज्य सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया थीं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े। राज्य सरकार ने ईमानदार और पारदर्शी प्रयासों से पिछले अढ़ाई वर्ष में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रा तिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का, गेहूं और जौ सहित पशुपालकों को दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है, जबकि पंजाब ने अब तक इसे लागू नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधारों के सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने क्षेत्र के मुद्दों को सक्रियता से उठाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की सराहना की। उन्होंने 250 करोड़ रुपये की लागत से विकासनगर में एक बहुउद्देश्यीय परिसर के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस भवन में पार्किंग की सुविधा सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय होंगे।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिमला शहर की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं और उन्हें हल करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने खराब मौसम के बावजूद कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिमला नगर निगम के पार्षदों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री से न्यू शिमला में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि न्यू शिमला में एक आधुनिक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा और हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता की सराहना की।

स्थानीय पार्षद आर.आर.वर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और नई पार्किंग सुविधा के लिए आभार व्यक्त किया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, एपीएमसी के अध्यक्ष देव आनंद वर्मा, पार्षद और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता अभियान का शुभारंभ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एचपीएसएसीएस द्वारा चार माह तक चलने वाले एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान आरम्भ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने किया।

राजीव कुमार ने बताया कि इस जागरूकता अभियान के दौरान प्रतिदिन विभिन्न वेब चैनलों और पोर्टलों के माध्यम से एचआईवी एड्स से संबंधित जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति जागरूक करना है।

यह डिजिटल अभियान विशेष रूप से युवाओं और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को लक्षित करेगा, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह पहल न केवल एचआईवी संक्रमण को रोकने में सहायक होगी, बल्कि इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को कम करने में भी मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का यह प्रयास प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सत्य कायम रहता है, भले ही उसे जनता का समर्थन न मिले। यह आत्मनिर्भर है।

......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

अपने ही उठाये सवालों में उलझे मोदी

पहलगाम आतंकी हमले के लिये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने और उससे बदला लेने के जिस तरह के संकल्प प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने देश के सामने लिये हैं उसके मुताबिक तो अब तक बहुत कुछ घट जाना चाहिये था। लेकिन कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने के अतिरिक्त अभी तक और कुछ नहीं हुआ है। पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी इस चूक को स्वीकारने के बाद भी इसके लिये न तो किसी को चिन्हित किया गया और न ही किसी को दण्डित किया गया। जबकि इस चूक ने 28 लोगों की जान ले ली है। यही नहीं इस घटना के बाद जिस तरह से कुछ मीडिया मंचों ने इसमें हिन्दू-मुस्लिम का वर्ग भेद खड़ा करते हुये जम्मू-कश्मीर के हर मुसलमान को इसके लिये जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया वह अपने में बहुत ही गंभीर हो जाता है। फिर एक यूटयूब चैनल 4 पीएम न्यूज़ और लोक गायिका नेहा ठाकुर के खिलाफ मामले दर्ज किये गये उससे कुछ और ही संकेत उभरते हैं। इस सारे परिदृश्य को समझने के लिये कुछ और सवाल उठाने आवश्यक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कभी संघ के प्रचारक हुआ करते थे। प्रचारक से वह चौदह वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे उनके शासनकाल में जिस तरह की स्थितियां गुजरात में बन गयी थी उनके साथ में अमेरिका ने उन्हें अपने यहां आने का वीजा नहीं दिया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गये तब अमेरिका से उनके रिश्ते किस तरह के रहे यह पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह भाजपा के पर्याय हो गये। मोदी है तो मुमकिन है यह संज्ञा उनको दी गयी। एक व्यक्ति के जीवन में चौदह वर्ष मुख्यमंत्री और फिर ग्यारह वर्ष प्रधानमंत्री होना अपने में ही एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज उसी प्रधानमंत्री के काल में भाजपा अपना नया अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक पहुंचे मोदी के ही काल में संघ की भाजपा के लिये आवश्यकता पर भी सवाल उठे हैं और आज तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं आ पाया है। यहां यह भी जिक्र करना आवश्यक हो जाता है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब केन्द्र की कांग्रेस सरकार से सार्वजनिक मंचों पर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने और आतंकवाद पर जिस भाषा में सवाल पूछते थे आज भी वही सवाल उसी भाषा में मोदी और उनकी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनके द्वारा पूछे गये हर सवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। आज देश की आर्थिक स्थिति और विकास पर मोदी सरकार का हर दावा वहां आकर खोखला हो जाता है जब आज भी 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग अपने राशन तक का जुगाड़ न कर पा रहे हों। उन्हें सरकार के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा हो। इस वस्तुस्थिति में यदि पहलगाम प्रकरण पर हिन्दू मुस्लिम करने के प्रयासों पर गंभीरता से विचार किया जाये तो उसकी गहराई में देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का सच ही सामने आता है। मोदी के प्रधानमंत्री के अब तक के कार्यकाल पर यदि नजर डाली जाये तो इस दौरान उनका हर फैसला ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार पर निर्भर करने का रहा है ताकि यह लोग ध्वनि मत से उनके फैसले का समर्थन करते रहें। लेकिन आज देश मोदी से उन्हीं की भाषा में उनके ही सवालों को उनके आगे परोस रहा है। इसलिये पहलगाम और वक्फ संशोधन पर उठते सवालों के परिदृश्य में यह नहीं लगता है कि सरकार कोई और बड़ी कारवाई करके देश का बिना शर्त समर्थन हासिल कर पायेगी। क्योंकि भ्रष्टाचार के जिस आन्दोलन के सहारे भाजपा केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई थी आज उस आन्दोलन के केंद्रीय सवाल 2G स्पैक्ट्रम और कॉमनवैल्थ घोटाले इस सरकार में बुरी तरह से बेनकाब हो गये हैं।

सड़कों पर नमाज पढ़ना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल, मेरठ पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लोग मस्जिद या फिर ईदगाह में नमाज पढ़ें। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने ईद से पहले सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी और सड़क पर नमाज पढ़ने को गैरवाजिब बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाएगा तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। मेरठ के पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि ईद की नमाज मस्जिदों या फिर ईदगाहों में अदा की जानी चाहिए। किसी को भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए।

मेरठ पुलिस ने सड़कों पर नमाज को प्रतिबंधित कर एक नयी बहस छेड़ दी है। यदि इसे इस्लामिक चश्में से देखा जाए तो भी यह जायज नहीं है। एक बार लखनउ स्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा की सामने वाली सड़क के बीचोबीच एक युवक नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों इस मामले को लेकर बड़ी बहस हुई थी। इसी बहस के दौरान देवबंदी उलेमाओं ने भी इस प्रकार के नमाज का विरोध किया था। देवबंद के तत्कालिन मुफ्ती अहमद ने बाकायदा बयान जारी कर कहा था कि इस प्रकार के नमाज को किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

कई इस्लामिक पवित्र ग्रंथों में सड़कों पर बैठने, आपस में बात करने और सड़कों को अवरुद्ध करने को नाजायज बताया गया है। यहां तक की एक स्थान पर तो यह भी लिखा है कि सड़कों पर पड़े किसी प्रकार के अवरोधकों, जैसे-पत्थर आदि को हटाना धर्म के अनुकूल कार्य है। यहां तक कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर बैठता है तो उसे अपनी नजर नीची करके रखनी चाहिए। ऐसे में सड़क को बाधित कर नमाज पढ़ना इस्लामिक कृत्य कैसे हो सकता है।

इसका एक पक्ष यह भी है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। भारत इस्लामिक देश नहीं है। न ही यहां सरिया को कानून का दर्जा प्राप्त है। भारत बहुसांस्कृतिक एवं बहुपांथिक देश है। यहां मुसलमानों के अलावे और कई समुदाय के लोग रहते हैं। यदि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ने लगेंगे और उन्हें छूट दे दिया जाएगा तो ऐसे ही हिन्दू भी अपने धार्मिक कार्य सड़कों पर करने की कोशिश करेंगे। यहां बड़ी संख्या में ईसाई भी रहते हैं। वे भी ऐसा करने का सोचेंगे। जैन, बौद्ध, सिख आदि भी ऐसा ही कुछ करना चाहेंगे तब उस सड़क का क्या होगा? फिर कहीं एक ही साथ सब सड़क पर उतर आए तो आपसी गतिरोध स्वाभाविक रूप से होगा। यह गतिरोध संघर्ष में भी बदल सकता है।

सड़कों को आम लोगों के लिए बनाया गया है। सड़कें यातायात के लिए है, इवादत के लिए नहीं है। इवादत के लिए इवादतगाह है। इवादत वहीं होनी चाहिए जहां उसका स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इवादत की व्यवस्था खंडित होती है। दुनिया के किसी भी धर्म में सड़कों पर इवादत करने का कोई विधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह भारतीय कानून के अनुसार गैर कानूनी भी है। इसलिए मुसलमानों को इस मामले में संयम बरतने की जरूरत है। साथ ही मुस्लिम संगठनों को चाहिए कि इस विषय पर वह अपना संदेश प्रसारित करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और सामाजिक सौहार्द कमजोर होगा।

भारत निर्वाचन आयोग की तीन नई पहल

शिमला। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है। ये उपाय इस वर्ष मार्च में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान परिकल्पित पहलों के अनुरूप हैं।

आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (वर्ष 2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। इससे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मृत्यु के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को फॉर्म 7 के अंतर्गत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना, क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से सूचना का पुन: सत्यापन करने में सहायता मिलेगी।

मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी परिवर्तन करने का निर्णय किया है। मतदाता का सूची क्रमांक और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, साथ ही फॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को सुगमतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बीएलओ, जिन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी (2) के अंतर्गत ईआरओ द्वारा नियुक्त किया जाता है, को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ आत्मविश्वास से बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और भारत निर्वाचन आयोग के बीच पहले इंटरफेस के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर दौरा करते समय बीएलओ जनता के लिए आसानी से पहचाने जा सकें।

कैशलेस भुगतान के लिए बस यात्रियों की पसंद बन रहा परिवहन निगम का एनसीएमसी कार्ड

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्री यूपीआई, क्रेडिट व डेबिट कार्ड सहित नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से भी टिकट राशि का भुगतान कर सकेंगे। मैट्रो की तर्ज पर निगम की बसों में यह कार्ड चलेगा। वहीं यह कार्ड देश के अन्य राज्यों में भी चलाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस कार्ड से यात्री पार्किंग फीस सहित शॉपिंग भी कर सकेंगे।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देते हुए कैशलैस सेवा को आसान

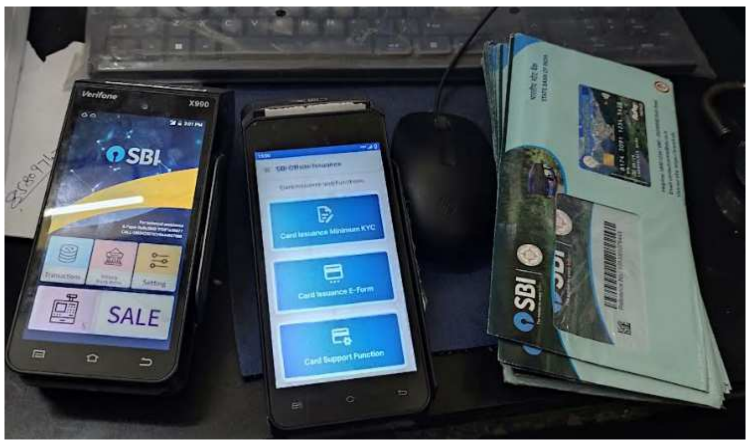

बनाने के लिए एचआरटीसी की बसों में एनसीएमसी कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। अब मैट्रो की तरह यात्री इस कार्ड का प्रयोग निगम की बसों में भी कर सकेंगे। वहीं यह कार्ड मुम्बई, दिल्ली में भी चलेगा, जिससे यात्रियों को बसों व मेट्रो में किराया देने के लिए कैश की जरूरत नहीं होगी।

एनसीएमसी कार्ड के लिए नहीं इंटरनेट की जरूरत

विशेष बात यह कि इस कार्ड को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यह कार्ड सबसे अधिक वहां काम आएगा जहां इंटरनेट सेवा धीमी रहती है या इंटरनेट सुविधा ही नहीं है। ऐसे में यात्री बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। निगम की बसों में चलने वाला यह एनसीएमसी कार्ड पहली बार मात्र 100 रुपए में बनेगा। इसके बाद व्यक्ति इसे अपने बैंक अकाउंट से रिचार्ज कर सकता है या फिर निगम के किसी भी बस काउंटर में जाकर टॉप अप (रिचार्ज) करवा सकते हैं।

कार्ड एक सुविधाएं अनेक

यह एक अंतर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है। परिवहन कार्ड उपयोगकर्ता को यात्रा, टोल शुल्क (टैक्स), पैसे निकालने और खुदरा खरीद के लिए भुगतान करने में भी सक्षम है। इस तरह यह एक छतरी के नीचे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एक साथ लाने के प्रयास के रूप में सामने आया है।

पांच साल होगी कार्ड की वैधता

हिमाचल पथ परिवहन निगम सरकाघाट के कार्यकारी क्षेत्रीय प्रबंधक विजय कश्यप ने बताया कि सरकाघाट डिपो में 19 अक्तूबर, 2024 को पहली बार उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए यह कार्ड उपलब्ध करवाया गया। अभी तक 138 कार्ड यहां बनाए जा चुके हैं। यह कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं। सरकाघाट बस स्टैंड में 100 रुपये की कीमत पर यह उपलब्ध हैं। यह कार्ड कम से कम सौ रुपये तथा अधिक एक हजार रुपये तक रिचार्ज किया जा सकता है। कार्ड की वैधता 5 साल की होगी।

निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ग्रीन व स्मार्ट कार्ड तथा महिलाओं को निगम की बसों में किराए में 50 प्रतिशत छूट के अलावा दिव्यांगजनों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यात्रियों के लिए एटीएम सुविधा भी आरंभ की गई है और यात्री कैश काउंटर पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

यात्रियों ने गिनाई एनसीएमसी कार्ड की खूबियां

सरकाघाट क्षेत्र से संबंध रखने वाले सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें अपने व्यवसाय के लिए परिवहन निगम की बसों में हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश से बाहर भी जाना पड़ता है। निगम द्वारा संचालित एनसीएमसी कार्ड से हमें काफी सुविधा मिल रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करता हूं।

क्षेत्र के एक अन्य व्यवसायी अशोक कुमार ने बताया कि हमें अपने कारोबार के कारण प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए निगम की बस सेवाओं का प्रयोग करता हूं। राज्य सरकार द्वारा निगम की बसों में कैशलैस सुविधा से हमें काफी फायदा हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूं।

नीति आयोग ने भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर रिपोर्ट जारी की

शिमला। नीति आयोग ने 'भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने' पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान आईएफसी के सहयोग से तैयार किया है। रिपोर्ट में वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुंच में व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई की अकूत संभावनाओं को उजागर करने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करती है। फर्म-स्तरीय डेटा और नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का उपयोग करते हुए। स्थायी एकीकरण को बढ़ावा देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके समावेश को बढ़ाने की बातें करता है। यह चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों-कपड़ा विनिर्माण और परिधान, रासायनिक उत्पाद, मोटर वाहन और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि भारत में एमएसएमई की क्षमता को अनलॉक करने के लिए क्षेत्र-विशेष की चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला जाता है। रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रीय और राज्य नीतियों की जांच करती है, वहीं यह कार्यान्वयन में गैप और एमएसएमई के बीच सीमित जागरुकता को भी उजागर करती है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक बात जो प्रमुखता से उभरकर सामने आई है वह यह है कि एमएसएमई की औपचारिक ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2020 और 2024 के बीच अनुसूचित बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई, जबकि मध्यम उद्यमों में 4 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इन सुधारों के बावजूद रिपोर्ट से पता चलता है कि एक बड़ा ऋण गैप अभी भी बरकरार है। वित्त वर्ष 21 तक एमएसएमई ऋण मांग का केवल 19 प्रतिशत औपचारिक रूप से पूरा किया गया था, जिससे अनुमानित 80 लाख करोड़ रुपए की मांग पूरी नहीं हो पाई। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का काफी विस्तार हुआ है लेकिन अभी भी इसकी सीमाएं हैं। ऋण गैप को खत्म करने और एमएसएमई के लिए समावेशी, स्केलेबल वित्त को अनलॉक करने के लिए रिपोर्ट में संस्थागत सहयोग और अधिक लक्षित सेवाओं द्वारा समर्थित एक नए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की मांग की गई है।

रिपोर्ट में एमएसएमई क्षेत्र में कौशल की कमी पर भी चर्चा की गई है। कार्यबल के एक बड़े हिस्से में औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, जो उत्पादकता को प्रभावित करता है और एमएसएमई की प्रभावी रूप से स्केल करने की क्षमता को सीमित करता है। कई एमएसएमई अनुसंधान और विकास आरएंडडी, गुणवत्ता सुधार या नवाचार में पर्याप्त निवेश करने में विफल रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट इस बात को फोकस करती है कि एमएसएमई को बिजली की भारी कमी, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और उच्च कार्यान्वयन लागत के कारण आधुनिक तकनीकों को अपनाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई के लिए बनाई गई राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद कई उद्यम या तो उनके बारे में नहीं जानते हैं या उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। क्लस्टरों के अपने विश्लेषण में पुरानी तकनीकों को अपग्रेड करना और मार्केटिंग और ब्रांडिंग क्षमताओं में सुधार करना प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि एमएसएमई को समर्थन देने वाली विभिन्न नीतियों और केंद्रीय बजट के माध्यम से एमएसएमई को हाल ही में दिए गए प्रोत्साहन के बावजूद, कम जागरुकता के कारण प्रभावशीलता में कमी आई है। नीति प्रभाव को बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में राज्य-स्तरीय मजबूत डिजाइन और कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है, जिसमें नीति विकास में निरंतर निगरानी, बेहतर डेटा एकीकरण और बेहतर हितधारक सहभागिता पर जोर दिया गया है।

भारत के एमएसएमई लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके, मजबूत संस्थागत सहयोग का निर्माण करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर सतत आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बन सकते हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी और प्रत्यक्ष बाजार संपर्को के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के माध्यम से एमएसएमई के लिए बेहतर समर्थन की मांग की गई है। खासकर भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी बेल्ट जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में। इसमें राज्य स्तर पर एक मजबूत और क्लस्टर-आधारित नीति ढांचे की मांग की गई है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है और एमएसएमई को समावेशी आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

नौकरी के पीछे भागने के बजाये भाग सिंह ने पुष्प उत्पादन कर चुनी आत्मनिर्भरता की राह

⇨ 1700 वर्ग मीटर भूमि पर फूलों की खेती से कमा रहे 10 से 12 लाख रुपये सालाना

शिमला। नौकरी के पीछे भागने के बजाये उच्च शिक्षित युवा अब खेती में कुछ अलग कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। उपमंडल गोहर के चरखा गांव के भाग सिंह इन्हीं में से एक हैं। कृषि में रूचि का आलम ऐसा कि आईटी सेक्टर की नौकरी को तिलांजलि दे अब पुष्प उत्पादन से आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त की है।

भाग सिंह बताते हैं कि उन्होने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विषय में पढ़ाई की है। कुछ समय आईटी क्षेत्र में नौकरी की, मगर मन कृषि क्षेत्र में ही रमा रहा। ऐसे में घर में ही पुश्तैनी जमीन पर बागवानी का फैसला किया। शुरूआत में पारंपरिक तकनीक से ही खेती-बाड़ी किया करते थे, जिसमें गेहूं, मटर, जौ, मक्की जैसी फसलें उगाते। कभी समय पर बारिश न होने, तो कभी ओले पड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे फसलों के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए।

खेती-बाड़ी में रूचि बहुत थी। ऐसे में हार मानने के बजाये बागवानी विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर परंपरागत खेती को आधुनिक खेती में बदलने का फैसला किया। उन्होंने पॉलीहाउस लगाकर फूलों की खेती करने का सुझाव दिया। विभाग द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया।

भाग सिंह ने शुरू में एकीकृत बागवानी विकास मिशन व हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष 2020 में तीन पॉलीहाउस लगाकर कार्नेशन फूलों की खेती शुरू की। अच्छी फसल व बाजार में बेहतर दाम मिलने पर वर्ष 2022, 2023 और 2024 में अतिरिक्त पॉलीहाउस स्थापित किए और कार्नेशन की खेती को विस्तार दिया। वर्तमान में वे लगभग 1700 वर्ग मीटर भूमि पर कार्नेशन, स्प्रे कार्नेशन, स्टोमा, जिप्सो किस्म के फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होने बताया कि वे कार्नेशन दिल्ली शहर में बेचते हैं। इससे प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है।

उन्होंने बताया कि पॉलीहाउस के निर्माण, फूलों की प्लांटेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्पोर्टिंग नेट इत्यादि पर अभी तक उनका कुल खर्च 20 लाख रुपए के लगभग हुआ है। इसमें लगभग 15 से 16 लाख रुपए सब्सिडी सरकार की ओर से प्रदान की गई है। इसके लिए उन्होने सरकार व विभाग का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रदेश सरकार के यह प्रयास सराहनीय हैं।

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना व एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत गोहर ब्लॉक में अभी तक 66 किसान पॉलीहाउस तकनीक से फूलों की खेती कर रहे हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन व हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष 2022 से अभी तक विभाग द्वारा लगभग 60 लाख रुपए की राशि उपदान के रूप में किसानों को प्रदान की गई है।

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष भर उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती करने के लिए पॉलीहाउस तकनीक का प्रशिक्षण कृषकों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाउस, शेड, नेट हाउस इत्यादि विधियां अपना कर फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि किसान राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मंडी की मांग के अनुसार विदेशी फूलों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें। युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुष्प परिवहन के लिए बस किराए में 25 प्रतिशत छूट और आवारा पशुओं से खेत को सुरक्षित रखने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ लगाने की लागत पर 85 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें फूलों की खेती के लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत उन फूलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन के तहत 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

देहात शिमला में बनेगे 14 और 17 मंजिला दो भवनो के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सात वर्ष का निरन्तर कार्यकाल पूरा कर लिया है।

बैठक में वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को वन अरण्यपाल (वन्यजीव) धर्मशाला के खाली भवन में स्थानातंरित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कारागार को मंडी से नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानातंरित करने की स्वीकृति दी गई। मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इस जेल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

बैठक में राजस्व विभाग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा आदि अन्य याचिकाएं ऑनलाइन प्राप्त एवं प्रसंस्कृत कर सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगाया जा सके।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में (जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है) रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में परिवहन सेवाओं के सुधार के दृष्टिगत स्थानीय मांग के अनुरूप प्रदेश में 350 नए स्टेज कैरिज रूट और अन्य अतिरिक्त मार्गों को 18 सीटर निजी टैम्पों ऑपरेटरों द्वारा संचालित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी। यह निर्णय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट्स, ब्लड बैंक तथा तृतीयक कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने फॉरेंसिक सेवाएं विभाग में फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मोहाल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो भवनों के वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक बेहतर डिजाइन लेआउट से युक्त विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया।

मंत्रिमंडल ने चरण-2 और चरण-3 के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने चंबा जिले के रेवेन्यू एस्टेट सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।

प्रतिभा सिंह ने जिला स्तरीय संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला स्तरीय संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में लोकतंत्र की मजबूती की जो नींव रखी थी उस नींव को भाजपा कमजोर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिये एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है और इसे उन्हें एकजुटता के साथ सफल बनाना है।

उन्होंने कहा कि देश में संविधान बचाओ, कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसे उन्हें सफल बनाना है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। उन्होंने ने पार्टी नेताओं से आग्रह है कि वह कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझे और उन्हें पूरा महत्व दे। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही बनती है और उनके परिश्रम को किसी भी स्तर पर अनदेखा नही किया जा सकता।

उन्होंने देश में जाति जनगणना के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहें थे जिसे अब केंद्र सरकार ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से सभी जाति के लोगों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे और यही बजह है कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला, ब्लॉक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनने जा रही है। पार्टी में उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा,जो पार्टी की मजबूती के लिये पूरी निष्ठा से कार्य कर रहें है।

उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ 10 मई तक जिला स्तरीय उसके बाद 11 मई से 17 मई तक हर विधानसभा यानी ब्लॉक स्तर का और उसके बाद 20 मई से 30 मई तक पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस अभियान के महत्व से लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से इस अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया।

बैठक में पूर्व मंत्री ठाकुर राम लाल, पूर्व विधायक बंम्बर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अंजना धीमान ने भी बैठक को संबोधित किया। बंम्बर ठाकुर ने पार्टी में अनुशासन पर जोर देते हुए बैठक में सर्वसम्मति से अहमदाबाद में पारित राहुल गांधी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

नवनियुक्त 'वन मित्रों' के लिए प्रशिक्षण मैनुअल जारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर, शिमला में नवनियुक्त 'वन मित्रों' के लिए प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। इस मैनुअल का उपयोग वन मित्रों को वन अग्नि प्रबंधन, विभागीय कार्यप्रणाली, नर्सरी प्रबंधन, विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों और समग्र वन प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। वन मित्र इस वर्ष 1 मई से 5 मई तक अपने-अपने रेंज में प्रशिक्षण लेंगे। सभी वन मण्डल अधिकारियों डीएफओ को प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो इसकी निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने मैनुअल को प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों को शीघ्र वितरित करने के निर्देश देते हुए दक्ष प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वन मित्र विभाग की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह जानकर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। उन्होंने प्रशिक्षण मैनुअल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 15 मई के बाद नवनियुक्त वन मित्रों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन विभाग को सशक्त करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए वन विभाग को आग की घटनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

वन मित्र भर्ती कार्यक्रम के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1,896 वन मित्र अपने-अपने स्थानों पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

7 मई को कुल्लू के शरची में आयोजित होगा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 7 मई, 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू कुल्लू जिला की तीर्थन घाटी के शरची में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यक्रम का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। राजस्व मंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए ही प्रदेश सरकार ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है।

सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित करने के निर्णय को सराहा

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और जिला शिमला से सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय की सराहना की।

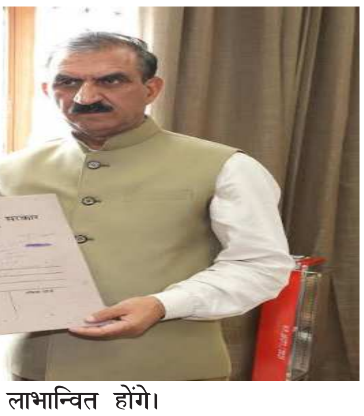

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि इन कार्यालयों के स्थानांतरण से प्रदेश की राजधानी में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के साथ-साथ कांगड़ा में समान विकास सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कई सरकारी भवन खाली पड़े हैं, जिनमें नदी गांव सहित लांजड़ी, सुधेड़, घरोह, चड़ी, सापड़, रिलू, कल्याड़ा और रैत ग्राम पंचायतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों को इन क्षेत्रों में स्थित भवनों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे इन पंचायतों के निवासी भी लाभान्वित होंगे।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उप-मुख्य सचेतक को आश्वासन दिया कि वह सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने के इन विकल्पों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहपुर की सीमा धर्मशाला से लगती है, इसलिए इन ग्राम पंचायतों में कार्यालयों को स्थानांतरित करने से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

हिम केयर से इलाज की सुविधा को बहाल करे सरकार: जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

ने कहा कि सरकार हिम केयर से इलाज की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बहाल करे। लोग अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं और अस्पतालों का भारी भरकम बिल न दे पाने के कारण बिना इलाज या आधे अधूरे इलाज के साथ वापस जा रहे हैं। जान पर बन जाने के बाद लोग मजबूरी में उधार लेकर इलाज करवाने को विवश हैं। आये दिन मेरे पास भी लोगों के फ़ोन आते हैं। सब एक ही बात कहते हैं कि आपका हिम केयर कार्ड चल नहीं रहा है। इलाज के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। पचास हज़ार जमा करने को कहा है, एक लाख जमा करने को कहा है। लोग पूछते हैं कि पैसे कहां से लाऊं? कैसे इलाज करवाऊं? जब सरकार कह रही है कि हिम केयर बंद नहीं हुआ है तो सरकारी अस्पतालों में चल क्यों नहीं रहा है? लोगों के इलाज क्यों नहीं हो रहा है। लोग फ़ोन करके सिर्फ़ अपना ही दुख-दर्द नहीं बताते बल्कि अपने साथ अस्पताल में एडमिट लोगों की समस्या भी बताते हैं। लोगों के सवालों के मेरे पास जवाब नहीं होते हैं। एक भी प्रदेशवासी अपना इलाज करवाने में लाचार न रहे इसलिए पूर्व सरकार में हमनें हिम केयर की व्यवस्था की। लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के साथ नाइंसाफी करने के साथ-साथ बीमार लोगों के साथ भी नाइंसाफी कर रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज में हिम केयर कार्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसे मरीज जिन्हें तत्काल इलाज, ऑपरेशन, स्टंट आदि लगाने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी कोई मदद नहीं मिल रही है। हिम केयर होने के बाद भी उन्हें इलाज के लिए पैसे जमा करवाने को कहा जा रहा है। पैसा नहीं तो इलाज नहीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए क़र्ज़ ले रहे हैं। क्या इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात सरकार द्वारा की गई थी। सरकार से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करें कि प्रदेश के लोग इलाज के लिए बेबस न नज़र आयें और लोगों को हिम केयर से निर्बाध इलाज मिलता रहे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन कोई न कोई शुल्क लगा रही है। अब अस्पतालों में पर्ची, भर्ती मरीजों के एक्स रे, ईसीजी की फीस वसूलने जा रही है। नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के शुल्क में भी वृद्धि कर दी है। हर जगह शुल्क लगाने के बाद भी सुविधाओं में कहीं कोई सुधार नहीं है। प्रदेश में हर तरफ़ अराजकता का माहौल है। प्रदेश सरकार के खिलाफ़ प्रदेश का हर वर्ग सड़क पर है।

आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कारवाई का समय:डॉ.राजीव बिंदल

शिमला/शैल। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुये आतंकी हमले में 27 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या

के विरोध में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किये। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में सी.टी.ओ. चौक पर विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजे।

उन्होंने कहा कि अब निर्णायक और प्रतिशोधात्मक कारवाई समय की मांग है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध तीव्र कूटनीतिक कदम उठाये हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत में अधिकृत अथवा अनधिकृत रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक को देश से बाहर निकाला जाएगा। देश के कई राज्यों में ऐसे नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक के स्वार्थ के लिए इन लोगों को संरक्षण दे रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है। उन्होंने कहा देश पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के दुष्परिणाम भुगत रहा है, अब अगर हिमाचल में भी यही गलती दोहराई गई तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ऐसे पाकिस्तानी नागरिक सामने आये हैं जो 20-25 वर्षों से अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके बच्चे वोटर बन गये हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यदि हिमाचल सरकार ने शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया, तो भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष छेड़ेगी।

नौणी विवि में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बागवानी, वानिकी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बागवानी, वानिकी, प्राकृतिक खेती, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि-व्यवसाय जैसे विविध में पढ़ाई करने के इच्छुक भावी छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन है, जहाँ विस्तृत विवरणिका भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

स्नातक कार्यक्रमों में, विश्वविद्यालय अपने मुख्य परिसर एवं नेरी और थुनाग में बागवानी और वानिकी महाविद्यालयों में बीएससी ऑनर्स बागवानी और बीएससी ऑनर्स वानिकी के कोर्स उपलब्ध है। मुख्य परिसर में छात्रों को बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी स्व-वित्तपोषण में प्रवेश लेने का भी विकल्प है। विश्वविद्यालय के नेरी महाविद्यालय में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय ने नौणी स्थित बागवानी महाविद्यालय और वानिकी महाविद्यालय और नेरी महाविद्यालय में एमएससी कार्यक्रमों की भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बागवानी में कीट विज्ञान, फ्लोरीकल्चर और लैंडस्केपिंग, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फल विज्ञान, मॉलेक्युलर बायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी, पादप रोग विज्ञान स्पाइस, औषधीय और सुगंधित फसलें, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सब्जी विज्ञान विषयों में बागवानी में एम एस सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमबीए कृषि-व्यवसाय प्रबंधन के पाठयक्रम का कोर्स भी छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विस्तार शिक्षा, कृषि सांख्यिकी, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, फॉरेस्ट बायोलॉजी और वृक्ष सुधार, वन उत्पाद और उपयोगिता, वन संसाधन प्रबंधन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सिल्वीकल्चर और एग्रोफोरेस्ट्री और मृदा विज्ञान विषयों में वानिकी में एम एस सी के लिए आवेदन किया जा सकता है।

स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई और स्व-वित्तपोषित सीटों के लिए 30 जून है। स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 जून है। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा की तारीख क्रमश: 15 जून और 5 जुलाई है। स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 जून जबकि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का परिणाम 11 जुलाई को घोषित किया जाएगा। स्नातक स्व-वित्तपोषण सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची 07 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी। स्नातक प्रवेश परीक्षा सोलन, हमीरपुर, सुंदरनगर, पालमपुर और रामपुर में आयोजित की जाएगी ।

स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जबकि स्नातक की स्व वित्त पोषित सीटों पर प्रवेश 10+2 परीक्षा में चार विषयों-अंग्रेजी, फ़िज़िक्स, कैमिस्ट्रि और बायोलॉजी/ गणित की मेरिट के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक सामान्य एवं स्ववित्तपोषित दोनों प्रकार की सीटों के लिए आवेदन कर सकता है।

रणधीर शर्मा ने मांगा मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा

शिमला/शैल। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री सुक्खू एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का इस्तीफा मांगा। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत बिलासपुर में हुई बैठक एवं बैठक में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की बैठक में जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह जनता के समक्ष निकल कर आयी उससे लगता है कि पूरे प्रदेश में संविधान बचाव नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी बचाओ अभियान चल रहा है और उसमें भी यह पार्टी पूरी तरह विफल है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश की जनता तो परेशान है ही पर उनके मंत्री भी परेशान है और वह उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। इसके साथ-साथ बिलासपुर में हुई बैठक के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि उनकी भी सुनवाई न तो प्रदेश की सरकार में है और न ही दिल्ली केंद्रीय आलाकमान के पास। सबसे बड़ी बात तो यह है की बैठक में विशेष समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये। इससे स्पष्ट है की विशेष समुदाय भी प्रदेश में कांग्रेस एवं सरकार से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रदेश का हर वर्ग मुख्यमंत्री से दुखी हो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये।

रणधीर शर्मा ने कहा कि जैसे की प्रतिभा सिंह भी मान चुकी है कि उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई न

तो हिमाचल प्रदेश में है न दिल्ली आलाकमान के पास तो उनको भी अपने पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जिस अध्यक्ष की सुनवाई न हो वह पद का क्या करेगी।

रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास अपने मित्रों, ओ एस डी, कैबिनेट मंत्री, पॉलीटिकल एडवाइजर के लिए तो पैसे हैं पर जनहित व विकास कार्यो के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान बचाओ अभियान में न बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद किया गया और न ही पहलगाम को लेकर दो मिनट का शोक रखा गया है।

कृषि को सशक्त बनाने के लिए कार्य योजना पेश

शिमला/शैल। खाद्य सुरक्षा और सस्ते भोजन के लक्ष्य को सतत कृषि समाधान के जरिये हासिल करने के उद्देश्य से, सिंजेंटा इंडिया ने विज्ञान आधारित बायोलॉजिकल उत्पादों के

माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए अपनी कार्ययोजना पेश की ।

मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार ने कहा, 'खेती कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पर्यावरण-अनुकूल और संतुलित खेती सुनिश्चित करने के लिए हमें बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी। नए बायोलॉजिकल उत्पाद हमारे उन सर्वोत्तम उपायों में से एक हैं, जो मिटी की गुणवत्ता को सुधारते हैं, फसलों की सहनशक्ति बढ़ाने और किसानों को समग्र समाधान देने के लिए बनाए गए हैं।

सुशील ने टेक्नॉलजी की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसान कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के प्रति जनता का दबाव, खेती के विकल्पों को और सीमित कर देता है। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने और उनके व्यवहार में बदलाव के कारण समाधान की प्रभावशीलता कम हो रही है, जिससे नई कार्यप्रणालियों की आवश्यकता है।

सुशील ने कहा, 'आधुनिक कृषि को साकार करने के लिए हमें नए उपकरणों की ज़रूरत है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास जरूरी है और नई तकनीक के बायोलॉजिकल एवं बीज उपचार इस बदलाव की अग्रिम पंक्ति में हैं।

सुशील ने कहा कि बायोलॉजिकल्स के तीन मुख्य टाइप्स बायोस्टिमुलेंट्स, पोषक तत्व उपयोग दक्षता वाले प्रोडक्ट और बायोकंट्रोल किसानों को प्रतिरोध प्रबंधन, मिटी की सेहत सुधारने, खाद्य में रासायनिक अवशेष घटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में अधिक विकल्प देते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट निष्कर्षहीन है सचिवालय के गलियारों में उठी चर्चा

> क्या ओंकार शर्मा ने मीणा को अपना पक्ष रखने का पूरा समय नहीं दिया?
> क्या यह रिपोर्ट उच्च न्यायालय के सामने आ पायेगी?

शिमला/शैल। क्या विमल नेगी प्रकरण पर बिठाई गई प्रशासनिक जांच निष्कर्षहीन है? क्या जांच अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा ने पावर कॉरपोरेशन के एम.डी. हरिकेश मीणा को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिये पूरा समय नहीं दिया? क्या सरकार इस जांच रिपोर्ट को प्रदेश उच्च न्यायालय में पेश नहीं होने देगी? यह सवाल इन दिनों सचिवालय के गलियारों में विशेष चर्चा का विषय बने हुये हैं? क्योंकि 20 मई को प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्व. विमल नेगी की धर्मपत्नी किरण नेगी की याचिका पर सभी प्रतिवादियों से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। स्मरणीय है कि विमल की मौत पर उनकी धर्मपत्नी किरण नेगी की शिकायत पर ही पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इस एफआईआर में सीधे तौर पर देशराज का ही नाम है और हरिकेश मीणा केवल पदेन नामित है। इसलिये परिजनों की शिकायत है कि जब प्रताड़ना का आरोप हरिकेश मीणा पर भी था तो उसे एफआईआर में पदेन क्यों लाया गया। फिर पुलिस किसी भी अधिकारी को जांच में तब तक शामिल नहीं कर पायी जब तक देशराज उच्च न्यायालय से होकर सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने में सफल नहीं हो गया। देशराज के बाद मीणा को भी उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी। इसी के साथ परिजनों के आरोप भी है इस जांच को लेकर। परिजनों का आरोप है कि जब नेगी की लाश भाखडा बांध एरिया से बरामद हुई तब उनको इसकी सूचना दूसरे दिन एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम के दौरान दी गयी। वहां भी अधिकारी पहले पहुंचे थे। फिर नेगी की लाश से जो सामान मिला है वह क्या और कहां है इसकी भी कोई जानकारी परिजनों को नहीं दी गयी है। इसी आचरण के आधार पर परिजनों को जांच की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है।

इसी सबके साथ इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सरकार ने इस प्रकरण की पुलिस जांच के साथ ही एक प्रशासनिक जांच भी आदेशित की थी। यह जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा को सौंपी गयी थी। ओंकार शर्मा ने यह जांच करके जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। स्वभाविक है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सरकार में यह जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को ही सौंपेगा। संयोगवश मुख्य सचिव प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। फिर इस प्रकरण में पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस तरह के आरोप पॉवर कॉरपोरेशन की कार्य प्रणाली पर इंजीनियर सुनील ग्रोवर ने ओंकार शर्मा के पास दी अपनी गवाही में लगाये हैं उनके परिदृश्य में मुख्य सचिव को इस मामले में ओंकार शर्मा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से परहेज करना चाहिए था क्योंकि वह स्वयं इसके अध्यक्ष भी हैं। फिर ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को शायद मुख्य सचिव ने निष्कर्षहीन रिपोर्ट की टिप्पणी दे दी है और यह कहा है कि इसमें मीणा कोअपना पक्ष रखने का पूरा समय नहीं दिया गया है। मुख्य सचिव की इन टिप्पणियों का शायद महाधिवक्ता से भी अनुमोदन करवा लिया गया है। ऐसे में जब यह रिपोर्ट निष्कर्षहीन मानी जा रही है तो इसे अदालत में पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के स्तर के अधिकारी की इतनी भारी भरकम रिपोर्ट ही निष्कर्षहीन है तो फिर सरकार में और कौन सा अधिकारी सक्षम होगा जो इस जांच को अंजाम दे पायेगा? ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदेश उच्च न्यायालय इस स्थिति में कैसे और क्या संज्ञान लेता है।

रोजगार नहीं, टैक्स की सरकार बन चुकी है कांग्रेस:बिक्रम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश आज कांग्रेस

की कुनीतियों का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। जहां एक ओर भाजपा सरकार के समय प्रदेश औद्योगिक निवेश का केंद्र बन रहा था, वहीं अब उद्योगपति पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं और सरकार मंदिरों पर टैक्स थोपकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर जजिया कर जैसा प्रहार कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में न उद्योगों के लिए माहौल बचा है, न रोजगार देने की इच्छाशक्ति, और न ही सरकार में नीयत साफ है। प्रदेश का आर्थिक भविष्य कांग्रेस के हाथों बर्बादी की ओर बढ़ रहा है।

बिक्रम ठाकुर ने कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल में आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बाहरी राज्यों से आये प्रतिष्ठित उद्योगपति उत्पादन बंद कर रहे हैं। 60% तक उत्पादन घट चुका है और सैकड़ों छोटे-बड़े उद्योगों पर ताले लगने की नौबत आ गयी है। यह स्थिति प्रदेश के हज़ारों परिवारों की आजीविका और युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक स्पष्ट दिशा थी। केंद्र सरकार की आई डी एस योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ था। लेकिन कांग्रेस की अक्षमता और उपेक्षा के कारण आज हिमाचल से उद्योग पलायन कर रहे हैं।

बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार धारा 118 का दुरुपयोग करके निवेशकों को हतोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में बैठे कुछ दलाल और 'चक्कर काटने वाले' इस प्रावधान का उपयोग केवल अपने खास लोगों को फायदा देने के लिये कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा को इन चेहरों की पूरी जानकारी है और समय आने पर इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा।

पूर्व मंत्री ने प्रदेश के उद्योग मंत्री से सीधे सवाल पूछा कि अब तक उनके विभाग ने कितने रोजगार दिये हैं? क्या उन्होंने कभी यह जांच की कि उद्योगों में 70% हिमाचली युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान लागू हो रहा है या नहीं? सरकार उन्हीं उद्योगों को परेशान कर रही है जो नियमों के भीतर काम करना चाहते हैं, जबकि चहेतों के लिए छूट और संरक्षण की नीति अपनाई जा रही है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार झूठ बोलने में माहिर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू स्वयं सदन में इस बात से मुकर गये कि कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी। अब मंत्रीगण भी इसी झूठ को दोहरा रहे हैं। जबकि विधानसभा अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस के मेनिफेस्टो को पढ़कर यह बात स्पष्ट कर चुके हैं और सरकार को फटकार भी लगाई थी।

उन्होंने सरकार पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुये कहा कि कांग्रेस सरकार मंदिरों पर टैक्स थोप रही है। पहले चिंतपूर्णी, नैना देवी जैसे शक्तिपीठों पर टैक्स लगाया गया और अब चुड़धार मंदिर मार्ग पर टैक्स वसूला जा रहा है। यह हिंदुओं की आस्था पर जजिया कर जैसा हमला है। 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में कांग्रेस सरकार खुलेआम आस्था का अपमान कर रही है। जिस जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी, आज उसी पर यह सरकार बोझ बन चुकी है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जब सरकार उद्योगों से राजस्व नहीं कमा पा रही तो अब वह श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से टैक्स वसूलने पर उतर आयी है। यह नीति आर्थिक भीख की तरह है। एक ऐसी सरकार की जो न रोजगार दे पा रही है, न विकास कर पा रही है।

प्रदेश को अब निर्णय लेना होगा वह कांग्रेस की झूठ, जजिया कर और उद्योग विरोधी नीतियों को सहता रहेगा या सच्चाई और विकास के रास्ते पर लौटेगा।